हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2025 को माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में विधान सभा भवन, तपोवन धर्मशाला में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

4-12-2025/1100/NS-AS/1

अध्यक्ष : प्रश्नकाल आरम्भ।

प्रश्न संख्या : 3393 (स्थगित)

श्री केवल सिंह पठानिया(उप-मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि प्रदेश में सीवरेज के लिए कितने पैसे खर्च किए गए और इसकी वस्तुस्थिति मांगी थी। उत्तर में बताया गया है कि 11933.83 करोड़ रुपये की सीवरेज के लिए पाइपें आई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में सीवरेज स्कीमों की अद्यतन स्थिति क्या है? कितनी स्कीमों का कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण हो गया है, कितनी स्कीमों का कार्य 50 प्रतिशत हो गया है और किस-किस शहर में 90 प्रतिशत से ज्यादा कार्य पूर्ण हो गया है? क्या आने वाले समय में उन स्कीमों को कंप्लीट कर दिया जाएगा? दूसरा, मैं मुख्य मंत्री जी व उप-मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने शाहपुर विधान सभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपये सैंक्शन किए थे। अध्यक्ष महोदय, जैसे ही टेंडर होता है तो सबसे पहले कार्य पाइपों की स्टोरेज को होना चाहिए। इसमें हिमाचल प्रदेश की जनता का पैसा लगा है। मैं उप-मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि विभाग ऐसा प्लान बनाए कि जिस सोर्स से पानी उठाना है या लिफ्ट इरिगेशन है उसको पहले डवलप किया जाए। यहां पर जो लिखित जवाब आया है उसमें बताया गया है कि वह डवलप नहीं हुआ है। करोड़ों रुपये की पाइपें ली गई हैं। इसके लिए डी0पी0आर0 भी बनी होगी। मेरा निवेदन है कि आने वाले समय में पैसा पहले सोर्स पर खर्च किया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चाहे जल जीवन मिशन या सीवरेज की स्कीम थी, मैं बताना चाहता हूं कि जिला कांगड़ा में इतना ज्यादा पैसा खर्च किया गया है लेकिन लोगों को फिर भी सुविधा नहीं मिली है। प्रश्न के क,ख,ग भाग के उत्तर में अत्याधिक धनराशि दर्शायी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश के 12 जिलों में सीवरेज के लिए कहां-कहां कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है? इसकी जिलावार डिटेल उपलब्ध करवाई जाए। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सीवरेज की किन स्कीमों का कार्य 80 प्रतिशत और 50 प्रतिशत कंप्लीट कर दिया गया है?

4-12-2025/1100/NS-AS/2

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता से अवगत हूं। 742 करोड़ रुपये की सीवरेज स्कीमों पर काम चल रहा है। ये मेजोरिटी ऑफ स्टेट की स्कीम्ज हैं। इसका पैसा भी राज्य सरकार को देना है। माननीय सदस्य ने मुख्य मंत्री जी से अपनी नजदीकियों के चलते 56 करोड़ रुपये की स्कीम स्टेट हैड में सेंक्शन करवा ली। मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए लगभग 20 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। उसमें से एक स्कीम में 7 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

04.012.2025/1105/RKS/AS-1

जल शक्ति मंत्री... जारी

और दूसरी स्कीम में अभी 80 लाख रुपये आए हैं। स्टेट हैड की स्कीम्ज का पैसा काफी देर से स्वीकृत होता है लेकिन आपकी स्कीम का फिर भी 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हमने पाइप्स पहले खरीद ली हैं। जब श्री जय राम ठाकुर जी के समय में जल जीवन मिशन आया था तो उस समय हजारों करोड़ रुपये के कार्यों को एक्सपीडाइट करने के लिए 15 करोड़ रुपये से ऊपर की स्कीमों के लिए ठेकदारों को पाइप्स खरीदने की इजाजात दी गई थी। इसके लिए आप भी कई बार कह चुके हैं और इस नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये पाइपें खरीदी हैं। आप कह रहे हैं कि पाइपें न खरीदी जाएं। जब ठेकदारों को कोई स्कीम आबंटित कर दी जाती है तो वह पहले पाइप्स खरीदता है या क्या करता है उसमें हमारा कोई दखल नहीं होता। आपने जो एक्शन लेने का सुझाव दिया है उसके लिए मैं सदन में कमिटमेंट नहीं कर सकता। क्योंकि जब कोई स्कीम आपने ठेकेदार को आबंटित कर दी तो यह उसकी प्राथमिकता है कि उसने आगे क्या करना है। आपकी स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ करना होगा, वह हम करेंगे।

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, ऊना में हमारे राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने मई, 2019 को पी0जी0आई0 सैटलाइट होस्पिटल बनाने की घोषणा की थी। उसके बाद आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी के समय उस होस्पिटल को बनाने के लिए लगभग 403 कनाल जमीन केंद्र सरकार को हस्तांतरित की गई थी। केंद्र सरकार की और से इस भवन को बनाने के लिए पौने चार सौ करोड़ रुपये जारी किए गए थे और यह कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है। यह कार्य दिसम्बर, 2025 या जनवरी, 2026 तक पूर्ण हो जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से बिजली, पानी, सड़क और सीवरेज की व्यवस्था करनी है। इन चार चीजों में सड़क और पानी की व्यवस्था तो हो गई है लेकिन सीवरेज के लिए जो 4.55 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाया गया था उसमें मात्र 1 करोड़ रुपये ही स्वीकृत हुआ है जिसके कारण यह सारा काम रूका हुआ है। इस प्लांट का अभी तक 20 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुआ है। मेरा आग्रह है कि माननीय मंत्री जी यह आश्वासन

04.012.2025/1105/RKS/AS-2

दें ताकि सीवरेज प्लांट के कार्य को पूर्ण करने के लिए 3,55,91,000 रुपये की राशि जल्द स्वीकृत हो जाए। उस होस्पिटल का भवन बनकर तैयार हो गया है। अगर वहां सीवरेज का काम लम्बित होगा तो होस्पिटल के संचालन में हमें काफी दिक्कत होगी। मेरा आग्रह है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए आप एकमुश्त पैसा जारी कर दें ताकि अस्पताल को हम समयबद्ध शुरू कर सके।

जल शक्ति मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ऊना में पी0जी0आई0 सैटलाइट होस्पिटल बन रहा है। एग्रीमेंट के अनुसार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के कार्य के लिए 4.55 करोड़ रुपये राज्य सरकार को देने हैं जिसमें से 1 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। मुख्य मंत्री जी के पास पास वित्त विभाग भी है। इसके बारे में इन्होंने भी कहा है और पी0जी0आई0 से हिमाचल काडर के आई0ए0एस0 ऑफिसर भी हमसे मिलने आए थे। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य के लिए जो 3 करोड़ रुपये की आवश्यकता है उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा। पी0जी0आई0 सैटलाइट होस्पिटल महत्वपूर्ण है इसलिए मेरा मुख्य मंत्री

जी से आग्रह है कि इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए शीघ्र राशि का प्रबंध किया जाए ताकि यह काम आगे बढ़ सके।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

04.12.2025/1110/बी.एस./डी.सी.-1

प्रश्न संख्याः 3393

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में चौपाल में सिरवेज का टैंडर लगा था यह 11.42 करोड़ रुपये का था और नेवरवा में 25.60 करोड़ रुपये का था। इसमें Administrative Approval & Expenditure Sanction आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार में दोनों स्कीमों में हो गई थी और टैंडर भी हो गए था। सिर्फ चौपाल का इसलिए अवार्ड नहीं हुआ कि फंड की कमी थी परंतु इन दोनों मैं फंड्ज थे। मेरे को जानकारी मिली है कि इनके फंड भी शिप्ट कर दिए गए हैं। मैं उप मुख्य मंत्री महोदय से यह विनती करना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में सिवरेज का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि नेरवा और चौपाल में सिवरेज का कार्य कब शुरू होगा? दोनों स्थानों में डी0पी0आर0 और AA&ES और नक्शा भी अप्रूवड़ है।

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया कि सिवरेज का जो काम है यह स्टेट हैड में चल रहा है और राज्य के पास इतना पैसा नहीं है कि इन स्कीमों को एक मुश्त फंडिंग की जा सके। मेरा माननीय सदस्य से आग्रह रहेगा कि केन्द्र में इनकी सरकार है वहां से पैसा सैंक्शंन करवाएं हम काम करवा देंगे। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की बात की वह तो मैंने देनी है और जब आदरणीय जय राम जी की सरकार थी तो तब भी मंत्री जी ने देनी थी। उसे तो आप करवा लेंगे। जब आप हमारे पास आएंगे और कहेंगे कि हम पैसे का बंदोबस्त कर लेंगे परंतु बाद में यह पैसा कहीं से मिलता नहीं है। यह जो 800 करोड़ रुपये की स्कीमें हैं यह पैसा स्टेट हैड से निकलने से रहा। मेरा मानना है कि आप इन स्कीमों को स्टेट हैड में मत डलवाइए। क्यों पैसा नहीं आएगा तो यह ऐसे ही लटकी रहेगी। इसलिए आप केन्द्र से पैसे का बन्दोबस्त करवाइए। आप इन्हें नाबार्ड में और अपनी प्राथमिकता में

भेजो ताकि कहीं से तो पैसा आए। ऐसे तो 10-15 साल तक ये स्कीमें लटक कर रह जाएंगी और कछुए की चाल से चलती रहेंगी। यह केवल हमारे समय की बात नहीं है, यह ओवर द इयर 10-15 सालों से चल रही हैं। इसलिए आप इन्हें किसी और हैड में डलवा करके इनमें पैसा दिलवाइए। आप हमें अपनी प्राथमिकत का पैसा दिलवा दो और हम इस कार्य को कर देंगे। लेकिन स्टेट से जितना पैसा आएगा उतना काम हम करवाते रहेंगे।

04.12.2025/1110/बी.एस./डी.सी.-2

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्री जी से पैसे के बारे में आश्वासन चाहा था परंतु मंत्री जी ने उस विषय को बड़ी चालाकी से मुख्य मंत्री की तरफ घुमा दिया क्योंकि वित्त विभाग उनके पास है। अब मैं सीधा मुख्य मंत्री जी से बात करता हूं। कृपया, आप बताएंगे कि यह पैसा कब तक दे दिया जाएगा? ताकि यह जो 400 बिस्तरों का अस्पताल है हम उसका जल्दी-से-जल्दी शुभारंभ कर सकें। क्योंकि यह ट्रीटमैंट प्लांट के बिना है और हम उस अस्पताल को शुरू नहीं कर पा रहे हैं। यदि मुख्य मंत्री जी ही उसमें इन्टरवीन करें तो 3 करोड़ 70 लाख 90 हजार रुपये रहा है इसके लिए आप आश्वासन दें ताकि हम इस कार्य को जल्दी-से-जल्दी शुरू कर सकें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ऊना में पी0जी0आई0 का सैटेलाइन सैंटर बन रहा है उसकी एनवायरनमैंट क्लीयरेंस से शुरूआत भी हमने ही कवाई थी। यह मामला दो साल पहले से पैंडिंग पड़ा था। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो भी सैंटर की स्कीमें हैं उनमें हमारे से कमिटमैंट ली जाती है कि आपको तभी पैसा दिया जाएगा जब आप इन-इन चीजों के लिए पैसा जमा करवाएंगे। जब यह पी0जी0आई0 सैटेलाइट सैंटर की बात आ रही है तो हमने कहा कि 30 करोड़ रुपया फोरेस्ट का, 15 करोड़ पानी का देंगे और 10 करोड़ रुपया और देंगे। केन्द्र सरकार कुल खर्चा करती है 80 करोड़ रुपया उसमें से 50 प्रतिशत राज्य का चला जाता है लेकिन जहां तक सिरवेज की बात है इसके लिए एक करोड़ रुपया दे दिया गया है। हम अगले बजट में देखेंगे कि अगर केन्द्र सरकार से कुछ उदार आर्थिक सहायता मिलती है तो हम बजट बनाते समय इसका पूरा ध्यान रखेंगे।

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप-मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में भरमौर छतराड़ी, मैहला और किलाड़ में सिवरेज का कार्या चल रहा है वहां पर सड़क खोद दी है, अब न इस कार्य को पूरा किया जा रहा है और

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

4.12.2025/1115/डी0टी0/डी0सी0 -1

प्रश्न संख्या 3393 जारी..

डॉ0 जनक राज जारी...

न ही उस सड़क को ही ठीक किया जा रहा है। मैंने पहले भी इस विषय को सदन में उठाया है। मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री जी से यह आश्वासन चाहुंगा कि सिवरेज के कार्य को भी पूरा किया जाए और साथ-ही-साथ जो सड़के खोद दी गई हैं जिसके कारण लोगों को चलने में असुविधा हो रही है उसका भी काम किया जाए क्योंकि लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के बीच में इन कार्यों को लेकर एक प्रकार का द्वंद्व चला हुआ कि क्योंकि जल शक्ति विभाग कहता है कि लोक निर्माण विभाग ने पैसा नहीं दिया और लोक निर्माण विभाग कह रहा कि जल शक्ति विभाग ने पैसा नहीं दिया, तो यह जो कंफयूजन है कृपा करके उसको दूर करें-ताकि मेरे चुनाव क्षेत्र में लोगों को जो असुविधा हो रही है, उसका समाधान हो सके।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, चम्बा आपका जिला भी है और माननीय सदस्य ने जो मसला उठाया उसको तो हम एग्जामिन करवा लेंगे कि वहां क्या स्थिति है। लेकिन मेरा माननीय सदस्यों से यह आग्रह रहेगा कि सिवरेज के मामले को आप अपनी एम0एल0ए0 प्राथमिकता में ही पोज करें। एम0एल0ए0 प्राथमिकता में आप लोग केवल पानी की स्कीम और सड़के ही पोज करते हैं और अगर सिवरेज भी उसी हैड में उठाएं तो अच्छा रहेगा क्योंकि स्टेट हैड में यह तो एक बार छप जाती है कि इसमें 80 करोड़ रुपये करवा लिया या 100 करोड़ रुपये का काम करवा लिया। स्टेट हैड से पैसा आता नहीं जिसके कारण 15-15, 20-20 साल से स्कीम्ज लटकी हुई हैं। इसलिए बेहतर यह है कि स्टेट हैड में सैंक्शन करवाने के बजाय ऐसी स्कीम्ज को एम0एल0ए0 प्राथमिकता में डालना चाहिए ताकि इसके लिए पैसा आ जाए। वह पैसा चाहे नाबार्ड से आए या किसी दूसरे सोर्सिस, यानी जहां से भी आए लेकिन ऐसी स्कीम्ज पर काम किया जा सके। यहां पर 742 करोड़

रुपये की स्कीम्ज की लिस्ट मेरे पास है। किसी विधान सभा क्षेत्र में कितनी राशि की स्कीम चल रही है उसका उल्लेख इस लिस्ट में है। मैंने इस लिस्ट में देखा कि सबका एक ही हाल है। एक साल में कितना पैसा आया दूसरे साल में कितना पैसा आया और तीसरे साल में कितना आया, इसमें यह सब लिखा है। इतने हाथ आप खड़े कर रहे हैं लेकिन मैं आपको कह दूं कि इनका जवाब एक ही है। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से यही कहूंगा कि सिवरेज की स्कीम्ज को आप नाबार्ड में पोज करें। क्योंकि जो 742 रुपये की बात मैंने कही ये सभी स्कीम्ज अभी कम्पलीट करनी है और इन्हें कम्पलीट करने का हम प्रयास करेंगे।

4.12.2025/1115/डी0टी0/डी0सी0 -2

Speaker : A detailed reply has been given by the Hon'ble Deputy Chief Minsiter and it is on the record also. ...(Interruption) Okay, I will allow last supplementary on this Questio. Shri Balbir Singh Verma Ji you may ask your supplementary.

श्री बलवीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री जी से यह विनती करना चाहता हूं कि क्या शहरी विकास में केंद्र सरकार के लिए हमारी चौपाल-नेरवा की प्रपोजल भेजेंगे?
उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह प्रपोजल भेजना तो फाइनेल्टि है। माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों से स्कीम की प्रपोजल तैयार करवा कर दोबारा भेजे और जब वह सचिवालय स्तर तक पहुंचेगी उसी के बाद ये हमारे साथ इस स्कीम के बारे में बात करें। पहले तो माननीय सदस्य इस स्कीम को पोज करें और सचिवालय स्तर तक पहुंएं। हमें इस स्कीम को केंद्र सरकार को भेजने में कोई आपत्ति नहीं है। माननीय सदस्य इस स्कीम के कागज पूरा करे दें हम उन्हें केंद्र सरकार को भेज देंगे।

4.12.2025/1115/डी0टी0/डी0सी0 -3

प्रश्न संख्याः 3449

श्री जीत राम कटवाल : प्रश्न संख्या 3449

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सूचना अभी एकत्रित की जा रही है।
अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का प्रश्न इसी विधान सभा सत्र में चौथी पार आ गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से विधान सभा सचिवालय से भी कहना चाहूंगा कि एक ही प्रकार के प्रश्नों को आपस में जोड़ कर एक ही प्रश्न के रूप में रखने चाहिए।

Speaker : These are postponed questions, but we will try that next time एक ही सब्जैक्ट मैटर के ऊपर जो प्रश्न होंगे, चाहे वह स्थगित प्रश्न हों, चाहे तारांकित प्रश्न we will fix them up in a tagged manner.

प्रश्नं संख्याः 3463

श्री सुधीर शर्मा : अनुपस्थित

अध्यक्ष : इस प्रश्न के लिखित उत्तर से माननीय आशीष शर्मा जी संतुष्ट हैं।

प्रश्न संख्या : 3765

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोद, एक तो मैं यह देख रहा हूं कि जो प्रश्न हम बार-बार पूछते हैं उन प्रश्नों के उत्तर पोस्टपोन होते रहते हैं, ऐसा क्यों? यह मेरा पहला प्रश्न है जिसका उत्तर यहां पर दिया गया है

श्री एन0जी0द्वारा जारी...

04.12.2025/1120/एच.के.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या - 3765

जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, यह मेरा पहला प्रश्न है जिसका यहां पर उत्तर दिया गया है।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष जी, आपके अन्य प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं। आप ऐसा मत बोलिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आज ही उत्तर आया है।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष जी, आज ही नहीं बल्कि हमेशा उत्तर दिया जाता है। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, हो सकता है उत्तर दिए गए होंगे लेकिन हमें मिल नहीं पा रहे थे।

अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न के "(क)" भाग में पूछा था कि दिनांक 31-12-2022 से दिनांक 31-10-2025 तक कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए और इनमें से कितने कर्मचारी एन0पी0एस0 से ओ0पी0एस0 में सम्मिलित हुए? इसके उत्तर में बताया गया है कि वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 और वर्ष 2025-26 (अक्तूबर-2025 तक) में कुल 26324 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष जी, आपकी जो क्वेरी है, वह भी इसमें शामिल है। इसके उत्तर में यह भी लिखा गया है कि "इनमें से 5356 सेवानिवृत्त कर्मचारी एन0पी0एस0 से ओ0पी0एस0 में गए हैं"।

04.12.2025/1120/एच.के.-एन.जी./2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि 5356 सेवानिवृत्त कर्मचारी जो एन0पी0एस0 से ओ0पी0एस0 में गए हैं, इनके कारण financial implications क्या हैं? यदि financial implications घटी हैं तो भी बता दीजिए और यदि बढ़ी हैं तो भी बता दीजिए। सबसे पहले भाग - "(क)" के संदर्भ में मैं यही जानकारी जानना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी इसकी सम्पूर्ण जानकारी हमें दे दें ताकि हम उसका आंकलन कर सकें कि कर्मचारियों को लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न के "(ख)" भाग में मैंने जॉब ट्रेनी के संदर्भ में पूछा था लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे अलग से पुछूंगा क्योंकि पहले भाग - "(क)" का जवाब मिल जाए तो बेहतर होगा, नहीं तो दोनों भागों के प्रश्न आपस में मैसअप हो जाएंगे।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष जी, प्रश्न का "(ग)" भाग भी एन0पी0एस0 व ओ0पी0एस0 से संबंधित है और आप उसके संदर्भ में पूछ सकते हैं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आप ठीक कह रहे हैं। प्रश्न के "(ग)" भाग के संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि एन0पी0एस0 कर्मचारियों ने ओ0पी0एस0 लेने के लिए कितना शेयर जमा करवाया है?

04.12.2025/1120/एच.के.-एन.जी./3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में लगभग 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को जिनकी पेंशन वर्ष 2003 के बाद बंद हो चुकी थी, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम देने का फैसला किया था। यह एक ऐतिहासिक फैसला था। इसमें पहली financial implication तो यह हुई है कि केन्द्र सरकार द्वारा हमें जो लगभग 1600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बोरइंग मिलती थी, वह ओ0पी0एस0 लागू करने के बाद बंद कर दी गई है।

अध्यक्ष महोदय, इसकी अन्य financial implications का हमारे राजस्व पर धीरे-धीरे दबाव पड़ना शुरू होगा। अभी हम 5356 कर्मचारियों को ओ0पी0एस0 दे रहे हैं। भविष्य में जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता जाएगा, हमारे कांग्रेस सरकार की नीति के अनुसार उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा हमारी सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24, वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 में जितने भी कर्मचारी लगे हैं और आने वाले समय में भी जो कर्मचारी लगेंगे, उन सभी के लिए हमारी सरकार ने फैसला किया है कि सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। इसका हमारे राजस्व पर धीरे-धीरे

दबाव पड़ेगा। अभी तो केवल 5356 को ही ओल्ड पेंशन दी गई है और आने वाले समय में जब और भी कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे तो ट्रेजरी पर और भी दबाव बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हमारी सरकार इसके लिए अपने संसाधन जोड़ रही है। हमारी सरकार ने संसाधन जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार भी किए हैं और निश्चित रूप से उनका फायदा हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों को मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यह फैसला हमने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया है। यदि यह फैसला हमने राजनीतिक लाभ के लिए लेना होता तो चुनावों से 6 माह पहले इसे लागू करते। यह फैसला हमने मानवीय, संवेदनशीलता और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से लिया है। 60 वर्ष के बाद जो भी सरकारी कर्मचारी

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

04.12.2025/1125/एच0के0-पी0बी0/1

प्रश्न संख्या 3765.......जारी मुख्य मंत्री ...जारी

उस आयु में कमाने लायक नहीं रहता है, उसे हर माह एक एश्योर्ड इन्कम निश्चित रूप से मिले ताकि वह अपने अंतिम सांस तक सम्मानजनक तरीके से अपने जीवन को जी सके। हमने ओ0पी0एस0 इस दृष्टिकोण से दी है। यदि हमें ओ0पी0एस0 से राजनीतिक फायदा लेना होता तो स्वभाविक रूप से हम इसे चुनाव के वक्त देते जैसे आपने (विपक्ष) भी चुनाव के वक्त जून माह में 5000 करोड़ रुपये बांटे थे लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमारी सरकार की यह कमिटमैंट थी और यह हमारी पहली गारंटी भी थी जिसे हमने पहली कैबिनेट में पूरा किया। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी का उत्तर conflicting and confusing है। मैं इस बात को लेकर हैरान हूं कि मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने यह राजनैतिक लाभ के लिए नहीं किया है। इसका क्या अभिप्राय है? आपने गारंटियां चुनाव से पहले दी है। आप कह रहे हैं कि यदि हमने इससे राजनैतिक लाभ लेना होता तो हम

ओ0पी0एस0 चुनाव से 6 माह पहले लागू करते लेकिन चुनाव से 6 माह पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी।

मुख्य मंत्री : नेता प्रतिपक्ष जी, मैं अगले चुनाव से 6 माह पहले की बात कर रहा हूं।

श्री जय राम ठाकुर : आप यही बात स्पष्ट करें कि आप अगले चुनाव की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि अधिकारियों पर सरकार की ओर से बहुत दबाव है। सदन में हम बार-बार प्रश्न पूछ रहे हैं जिनके जवाब में सूचना एकत्रित की जा रही है, लिखा जाता है । आपने प्रश्न के भाग-ख का जवाब दिया है कि इस अवधि के दौरान कुल 8,436 नये पदों का सृजन किया गया। हमें यह बात तो समझ में आती है। अभी तक कितने लोगों को स्थायी कॉन्ट्रेक्ट एवं जॉब ट्रेनी पदों पर नियुक्ति दी गई, इसका ब्यौरा विभागवार उपलब्ध नहीं है यानी सूचना एकत्रित की जा रही है। (***)इसका मतलब है कि सूचना एकत्रित की जा रही है।

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

04.12.2025/1125/एच0के0-पी0बी0/2

अध्यक्ष महोदय, उत्तर के भाग-ग में भी यही लिखा है और इसमें पूरी डिटेल के बाद अंतिम में लिखा है कि परंतु वित्त विभाग के पास इनकी वर्षवार संख्या और जमा धनराशि का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। (***) इससे बेहतर यह होता कि आप यह कह देते कि सूचना एकत्रित की जा रही है। आपने जवाब में लिखा है कि भाग-क,ख,ग की सूचना सभा पटल पर रख दी गई है लेकिन सभा पटल पर पूर्ण सूचना नहीं है। उत्तर के भाग-ख व भाग-ग में कहा गया है कि जब सूचना आएगी तब आपको उससे अवगत करवा दिया जाएगा जिसका अभिप्राय यह है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। जवाब के भाग-ग में सूचना उपलब्ध नहीं है और धनराशि का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। (***) अध्यक्ष महोदय, क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्न का जवाब पूर्ण रूप से विधान सभा में ले किया जाए।

उप-मुख्य मंत्री : नेता प्रतिपक्ष जी, आज आपका ध्यान बाहर है।

श्री जय राम ठाकुर : उप-मुख्य मंत्री जी, मेरा ध्यान सदन में ही होता है और सत्ता पक्ष की तरफ ही होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना जवाब देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो? यह आपकी अप्रूवल से होता है क्योंकि जब भी विधान सभा में प्रश्न लगता है उसके जवाब की अप्रूवल मिनिस्टर इंचार्ज से होती है और इस संदर्भ में वित्त मंत्री स्वयं मुख्य मंत्री जी हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है जिसमें आपकी भी सदन और माननीय सदस्यों को कोई डायरेक्शन होनी चाहिए।

Speaker : Aspersion on the Vidhan Sabha Secretariat will not be a part of the record. ...(Interruption) There is an aspersion. माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि हमने पहले भाग-क का पूरा जवाब दिया है। फिर नेता प्रतिपक्ष जी ने भाग-ग की बात की है लेकिन मैं इसकी कन्फयूजन में नहीं जाना चाहता हूं। वह मैं इनसे अलग से पूछ लूंगा। इन्होंने भाग-ख के बारे में भी पूछा है। मैं नेता प्रतिपक्ष जी को बताना चाहता हूं कि आपने भाग-ख में नये व्यक्तियों से संबंधित पूछा है कि आपने कितने पद

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

04.12.2025/1130/Y.K./A.P./01

प्रश्न संख्या 3765 जारी .....

मुख्य मंत्री जारी .....

लेकिन फिर इन्होंने प्रश्न के भाग-ग का भी पूछा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाग-ख नए भर्तियों से संबंधित है। आपने पूछा है कि कितने पदों को सृजित किया गया, कितने नए पद स्वीकृत किए गए और जॉब ट्रेनी के बारे में भी पूछा है। यही प्रश्न माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल का है, जो पिछले प्रश्नों से भी संबंधित है, लेकिन यह प्रश्न इसमें जुड़ा हुआ है। इसमें हमने यह कह दिया है कि हमने नए पद स्वीकृत किए हैं और विभागवार

ब्यौरा इन्हें बाद में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जब यह सारे प्रश्न आएंगे, हम उन्हें सदन में उपलब्ध करवा देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाग-ग में आपने पूछा है कि जो कर्मचारी ओ0पी0एस0 से एन0पी0एस0 में गए उनका शेयर कितना है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन में कहना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष ने सत्र के पहले दिन ही कह दिया था कि हम इस सरकार के सभी फैसलों की समीक्षा करेंगे। हमने जो ओ0पी0एस0 दिया है कर्मचारियों को, उसमें सरकार की तरफ से पूरा जवाब आ गया है। आप उनके शेयर के बारे में पूछ रहे हैं उनका शेयर 50-50 प्रतिशत जाता है। उनका शेयर ई0पी0एफ0 में 12 प्रतिशत होता था और सरकार का शेयर 14 प्रतिशत होता था, जो लगभग 10,000 करोड़ रुपये के करीब है। हमारे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का जो एन0पी0एस से ओ0पी0एस0 में शिफ्ट हुए हैं, उनका ई0पी0एफ0 के रूप में जो शेयर है, वह उनके पेंशन फंड में है। हमने बार-बार वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है कि हमें उस पेंशन फंड को वापस किया जाए और जिस कर्मचारी को ओ0पी0एस0 लागू होगी, उसका फंड प्रदेश के सरकारी खजाने में जमा करवाना होगा। ऐसा हमने इसमें लिखा है। मैं पूर्व मुख्य मंत्री को बताना चाहता हूं कि लगभग 10,000 करोड़ रुपये के करीब हमारा एन0पी0एस0 का शेयर, जो पेंशन फंड है, उसे शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। हमने केंद्र सरकार से यह भी कहा है कि जो कर्मचारी एन0पी0एस0 से ओ0पी0एस0 में आए हैं, उनका शेयर प्रदेश सरकार को दिया जाए। वह फंड अभी तक हमें नहीं मिला है। निश्चित तौर पर हमारा वित्त मंत्रालय से पत्राचार चल रहा है और जैसे ही हमें यह फंड मिल जाएगा तो हमारी सरकार आपकी सरकार के समय में जो शेष एरियर बचा था, उसे कर्मचारियों को दे देगी।

04.12.2025/1130/Y.K./A.P./02

लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि आपकी राज्य सरकार द्वारा एम0ओ0यू0 साइन किया गया था और उस एम0ओ0यू0 के तहत आप इसमें बंधे हैं। हमारी सरकार उस फंड को किसी-न-किसी तरह से लेने की कोशिश कर रही है।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार यह दावा करती है कि ओ0पी0एस0 लागू करके इन्होंने कर्मचारियों को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ दिया है।

जो आंकड़ा सामने आया है, उसके अनुसार तीन साल में कुल 26,324 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। जब यह पूछा गया कि इनमें से कितने कर्मचारियों ने एन0पी0एस0 के बजाय ओ0पी0एस0 को चुना, तो उसमें ओ0पी0एस0 की संख्या 5,356 है। इसका मतलब यह है कि लगभग 21,000 कर्मचारियों ने ओ0पी0एस0 के बजाय एन0पी0एस0 को प्राथमिकता दी है। तो क्या अब कर्मचारियों को एन0पी0एस0 में आर्थिक लाभ अधिक दिखाई दे रहा है? क्या कारण है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी ओ0पी0एस0 के बजाय एन0पी0एस0 को प्राथमिकता दे रहे हैं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसका पूरा लाभ वर्ष 2003 में 1,17,000 से लेकर 1,36,000 कर्मचारियों को हुआ है। जैसे-जैसे कर्मचारी सेवानिवृत्त होते जाएंगे, एन0पी0एस0 वाले कर्मचारी अपना शेयर जमा करवाते रहेंगे और निश्चित तौर पर उन्हें ओ0पी0एस0 मिलता रहेगा। यह शेयर सेवानिवृत्ति के साथ-साथ जुड़ता जाता है। इससे बहुत से लोगों को लाभ मिलेगा।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे प्रश्न का जबाव नहीं है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह खुद कन्फ्यूज्ड है। इन्होंने कहा कि 26,324 कर्मचारियों में से केवल 5,356 कर्मचारियों ने ओ0पी0एस0 चुना है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसे-जैसे कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं, वे एन0पी0एस0 से अपना पैसा अंशदान के रूप में जमा करवाते हैं और उसके बाद ओ0पी0एस0 में शिफ्ट होते हैं। अभी तक इतने ही कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं।

अध्यक्ष : ...(व्यवधान) माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी, आप बैठ जाओ। माननीय मुख्य मंत्री जी को पहले जबाव तो देने दो।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय,

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

04.12.2025/1135/AT/YK/01

प्रश्न संख्या 3765 जारी .....

मुख्य मंत्री जारी...

मैं आपको बार-बार कह रहा हूं कि वर्ष 2022-23 में जिन्होंने ओ0पी0एस0 में ज्वाइन किया, उनमें एन0पी0एस0 से कुल 26,000 में से 5,356 कर्मचारी ओ0पी0एस0 में गए हैं। पिछले 3 साल में इतने लोग रिटायर हुए हैं और आगे जो रिटायर होंगे, वह भी ओ0पी0एस0 में ही जाएंगे। क्योंकि ओ0पी0एस0 में जाने के लिए एन0पी0एस0 का अंशदान राज्य सरकार ने ट्रेजरी में जमा करवाया है, उसी आधार पर उन्हें ओ0पी0एस0 लागू होती है। इसी कारण संख्या आगे बढ़ती जाएगी। यह बात मैं आपको बार-बार कह रहा हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्षः अब मुझे जवाब में समझने और समझाने में कहीं अंतर लग रहा है। इसमें पूरी डिटेल है। There is technical confusion. ...(Interruption) माननीय रणधीर शर्मा जी।

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि या तो प्रश्न का उत्तर गलत है या मुख्यमंत्री... (व्यवधान)

अध्यक्षः आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री रणधीर शर्माः सर, प्रश्न पूछा था, उसी का जवाब नहीं आया। ...(व्यवधान) जब कर्मचारी सेवा-निवृत होते हैं वे तभी लिखकर देते हैं कि उन्हें एन0पी0एस0 में रहना है या ओ0पी0एस0 में जाना है। उसके बाद ही वह पैसा ट्रेजरी में आएगा। तो आपका जवाब है कि 3 सालों में 26,324 कर्मचारी रिटायर हुए। 3 साल में 5,356 कर्मचारियों ने ओ0पी0एस0 अडोप्ट किया।

अध्यक्षः नहीं-नहीं, यह अलग है। इसका पार्ट अलग है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों में एन0पी0एस0 से ओ0पी0एस0 5,000 कर्मचारी में गए।

04.12.2025/1135/AT/YK/02

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, एन0पी0एस0 में तो सारे कर्मचारी आते ही हैं। जो रिटायर होने वाले हैं, वही माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछा था, उसी का जवाब दिया जाए।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री महोदय, इसे स्पष्ट कर दीजिए।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह फिर कन्फ्यूज हो रहे हैं और अपनी बात बार-बार फॉर्सफूली कह रहे हैं। आपके जवाब में लिखा है कि वर्ष 2022-23 में 7,053 लोग ओ0पी0एस0 में आए, वर्ष 2023-24 में 7,217 लोग ओ0पी0एस0 में आए और वर्ष 2024-25 में 6,698 लोग ओ0पी0एस0 में आए। एक तो मैं यह बात बताना चाहता हूं और ये जो 5,396 लोग हैं, उन्होंने अभी एन0पी0एस0 से ओ0पी0एस0 अडोप्ट की है। यही इस प्रश्न का उत्तर है।

04.12.2025/1135/AT/YK/03

प्रश्न संख्या - 3766

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभापटल पर रखी गई है, उससे मैं लगभग संतुष्ट हूं। फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि क, ख, ग और घ में मैंने एक पुल और चार सड़कों की बात की है। मैं चाहूंगा कि इस वित्तीय वर्ष में इन तीन सड़कों और संबंधित पुल के लिए बजट का प्रावधान किया जाए। ये सभी सड़कें काफी पुरानी हैं और बारिश के कारण जो आपदा आई थी उसमें इनको काफी नुकसान हुआ है। यह क्षेत्र मेरे दूर-दराज के चिड़गांव इलाके से संबंधित है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इसके लिए जल्द से जल्द बजट का प्रावधान किया जाए।

लोक निर्माण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र की जिन चार सड़कों की बात की है, लाल पानी-धूमरेडा, देवीधार-भमावाड़ी, चिड़गांव-पुजारली, चिड़गांव-आंध्रा-गुशाली ये चारों सड़कें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। पिछली बार इसका कुछ अंश चिड़गांव-पुजारली सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

के अंतर्गत वर्ष-2020 में पूर्ण किया गया था और इसकी पंचवर्षीय नियमित रख-रखाव अवधि जुलाई वर्ष- 2025 में समाप्त हुई है। इस वर्ष भी इसमें नुकसान हुआ है, इसको हम अगले वर्ष ऐ0एम0पी0 में लेने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसे हमने एक सड़क PMGSY-4 में प्रपोज भी की है।

एम0डी0द्वारा जाारी.....

04-12-2025/1140/AG/MD/1

प्रश्न संख्याः 3766--जारी

लोक निर्माण मंत्री---जारी

यह मेरा निवेदन है कि हमारी कई सड़कें इसमें और पूरे प्रदेश में शामिल हो सकती थीं, लेकिन हम वर्ष 2011 की जनगणना को ही सभी मानकों के लिए आधार मान रहे हैं। इसी कारण वास्तविक आबादी बढ़ जाने के बावजूद हम चाहकर भी इन सड़कों को उस सूची में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। because of the last census that was conducted in 2011, वैसे तो मेरा सरकार से, माननीय मुख्य मंत्री जी से और सभी संबंधित अधिकारियों से निवेदन रहेगा और मैं इस विषय पर अलग से भी चर्चा करूंगा कि इसे प्राथमिकता में रखते हुए केंद्र सरकार को अनुरोध भेजा जाए कि अगली जनगणना जल्द से जल्द करवाई जाए। क्योंकि पिछली जनगणना के आधार पर ही कई विकासात्मक गतिविधियां तय हो रही हैं, और पुराने मापदंडों के कारण हमारी कई सड़कें पात्र नहीं हो पा रही हैं। इसका प्रदेश को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिए यह मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम अवश्य उठाए, यह मैं माननीय सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं।

प्रश्न संख्या : 3767

अध्यक्ष : श्री विपिन सिंह परमार (अनुपस्थित)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर जबाब देना चाहता हूं।

अध्यक्ष : प्रश्न पूछने वाले ही अनुपस्थित हैं, क्या आप फिर भी जबाब देना चाहते हैं?

मुख्य मंत्री : नहीं-नहीं, आपने पूछा तो मैं इस पर बोलना चाहता हूं।

04-12-2025/1140/AG/MD/2

अध्यक्ष : Hon'ble Chief Minister wants to reply in the absence of the Member.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, सदस्य की अनुपस्थिति में मुख्य मंत्री जी उत्तर बाद में दे सकते हैं।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, आप प्रश्नकाल के बाद इस बारे में स्टेटमैंट दे देना।

श्री जय राम ठाकुर : जी बिल्कुल, आप बाद में इस पर स्टेटमैंट दे सकते हैं।

मुख्य मंत्री : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप दो मिनट बैठ तो जाइए। मुझे दो मिनट बोलने दीजिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह चीज व्यवस्था के खिलाफ है।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, आप 12.00 बजे इस पर स्टेटमैंट दे देना कि इस प्रश्न से मुतलिक मैं इस माननीय सदन में सूचना देना चाहता हूं।

04-12-2025/1140/AG/MD/3

प्रश्न संख्या : 3768

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि सरकार द्वारा वर्ष 2024 से खिलाड़ियों को 200 किलोमीटर तक ए0सी0थ्री0-टियर और 200 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए इकोनॉमी क्लास की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से

जानना चाहता हूं कि हाल ही में स्कूल स्तर की राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता, जो अंडर-17 बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अरुणाचल प्रदेश के इटानगर में दिनांक 24-10-2025 से 4-11-2025 तक आयोजित की गई, उसमें हमारे जो खिलाड़ी गए थे, उन्हें यह सुविधा क्यों नहीं दी गई? आपने कहा कि यह सुविधा देना शुरू कर दिया गया है तो यह किस स्तर से लागू की गई है? क्या यह सुविधा इंटर-यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों को भी मिल रही है? क्या वर्ष 2017 से शुरू होने वाले मोदी जी की सरकार द्वारा संचालित खेलो इंडिया यूथ गेम्स तथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी यह सुविधा प्रदान की जाएगी? मैं इन सभी बिंदुओं पर माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

आयुष मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी ने जो प्रश्न उठाया है, उसके संबंध में मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि स्कूलों के जो खिलाड़ी बाहर गए थे, उनमें से किसी ने भी स्पोट्र्स विभाग के पास यह आवेदन नहीं किया कि वे दूसरे राज्य में जा रहे हैं या उन्हें किसी सुविधा की आवश्यकता है। यदि आपके संज्ञान में इस प्रकार का कोई मामला है तो वह स्पोर्टस डिपार्टमेंट के पास एप्लाई कर दें और जो अपने खर्चे पर बाहर गए हैं उनको हम रिवर्समैंट बेसिज़ पर उनका खर्चा हम सरकार के माध्यम से वापिस कर देंगे।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---

04.12.2025/1145/केएस/एजी/1

आयुष मंत्री जारी ---

दूसरे, जो माननीय सदस्य ने खेलो इंडिया की बात की कि आदरणीय मोदी जी ने वह स्कीम चलाई है और उसके माध्यम से कोई बजट आ रहा है, मैं इस माननीय सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि खेलो इंडिया स्कीम के माध्यम से हमारे पास अभी तक कोई बजट नहीं आया है। अगर निकट भविष्य में आएगा तो उसको समान रूप से वितरित किया जाएगा।

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा अभी जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी भारत की टीम ने कबड्डी का विश्व कप जीता है, उसमें हिमाचल प्रदेश की हमारी पांच खिलाड़ी पहली सात की टीम में थीं और उसके साथ-साथ बॉक्सिंग, हैंडबॉल, वॉलीबॉल में भी हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपने नोटिफिकेशन कर दी कि 200 किलोमीटर तक हम ए0सी0थ्री-टियर देंगे और उससे ऊपर इकॉनोमी क्लास एअर फेयर देंगे तो उसके बाद भी यह इम्पलीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? मैं जानना चाहूंगा कि आपने इसकी नोटिफिकेशन किस तरह से की है? उसकी कॉपी हमें भी तथा प्रत्येक स्कूलों, कॉलेजों और युनिवर्सिटीज़ भी दी जाए ताकि जब भी हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी कहीं पर भी राष्ट्रीय स्तर के खेलों में जाए तो उनको सुविधा मिल सके। क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने स्पोर्ट्स में अच्छा नाम कमाया है। डाइट मनी के बारे में आपने कहा था कि हमने यह बढ़ाई है लेकिन इसी से सम्बन्धित मेरा एक और प्रश्न है। मैं जानना चाहूंगा कि डाइट मनी क्या आपने स्कूल के बच्चों के लिए ही बढ़ाई है या उससे ऊपर इंटर युनिवर्सिटीज़ के लिए या अन्य खेलों में भी बढ़ाई है? अध्यक्ष महोदय, हमारे हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को कहीं पर भी यह सुविधा नहीं मिल रही है। मेरा निवेदन है कि इसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए ताकि हमारे खिलाड़ियों को यात्रा करने के लिए अच्छी सुविधा मिल सके।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, यह यात्रा भत्ता से रिलेटिड है। अगर आपके पास दूसरी इन्फोर्मेशन है तो दे दें अन्यथा यह इस प्रश्न का भाग नहीं है।

आयुष मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि प्रदेश के मुख्य मंत्री ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में

04.12.2025/1145/केएस/एजी/2

अभूतपूर्व बदलाव ले कर आए हैं। हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि ओलंपिक्स, कॉमनवैल्थ गेम्ज़ और एशियन गेम्ज़ में हमारे जिन खिलाड़ियों ने हिमाचल का नाम प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश व दुनिया में रोशन किया था उनको लगभग 14.70 करोड़ के करीब-करीब सम्मानित राशि से शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम द्वारा

सम्मानित किया गया। जो माननीय सदस्य ने डाइट मनी की बात की, मैं बताना चाहूंगा कि 7 जून, 2024 को जो नोटिफिकेशन हुई है, उसके माध्यम से डाइट मनी सभी के लिए बढ़ाई गई है। दैनिक आहार भत्ता 240 रुपये से बढ़ाकर 250 किया गया था। राज्य के अंदर खेल प्रतियोगिताओं के लिए 240 रुपये से बढ़ाकर इसको 300 रुपये किया था। जिला स्तर पर इसको 400 रुपये किया गया था और राज्य और राज्य के बाहर जो खिलाड़ी जाते हैं, उनको सरकार द्वारा 500 रुपये प्रतिदिन डाइट मनी दी जा रही है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि ये डाइट मनी सभी के लिए बढ़ाई गई है और नियमित रूप से दी जा रही है। जो प्रदेश में इवेंट्स होते हैं या प्रदेश के बाहर होते हैं, उन सभी को यह डाइट मनी उपलब्ध करवाई जा रही है।

श्री संजय रत्न : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे ज्वालामुखी राजकीय महाविद्यालय की बेटी पिछले साल अमेरीका में, यू.एस.ए. से गोल्ड मैडल ले कर आई। परंतु मुझे बताया गया है कि अभी तक भी उसे सरकार से कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया, कोई ईनाम नहीं दिया गया। मैं माननीय युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो ऐसे बच्चे हैं, जो हिमाचल से निकलकर पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, जहां आप क्रिकेट के बच्चों को या

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

04.12.2025/1150/av/as/1

प्रश्न संख्या : 3768------- क्रमागत श्री संजय रत्न --------- जारी

दूसरी गेम्ज के खिलाड़ियों को इनाम देकर प्रोत्साहन देते हैं, तो क्या इंडिविजुअल गेम्ज में जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल लाकर हिन्दुस्तान और हिमाचल का नाम रोशन कर रहे हैं, क्या आप उनको भी ऐसा इनाम देने बारे विचार रखते हैं?

आयुष मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने बताया कि बोक्सिंग में एक लड़की जीतकर आई है, इन्होंने इस बारे में मुझसे बात भी की थी। इन्होंने जैसे बताया कि उस

लड़की को सम्मान राशि नहीं दी गई है। मैंने इनसे उस बारे में बात की थी और विशेष रूप से बताया भी था कि इसके पीछे न देने का क्या कारण है। **परंतु आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि इसमें बोक्सिंग को भी शामिल किया जाए। अगर किसी प्रदेश के खिलाड़ी ने देश व दुनिया में नाम कमाया है तो उसको भी सम्मान राशि दी जाएगी।** यहां पर जैसे राकेश जम्वाल जी ने कहा तो मैं इसमें यह भी बताना चाहूंगा कि इन्टर यूनिवर्सिटीज इत्यादि के लिए भी डाइट मनी बढ़ाई गई है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि खेल छात्रावास बिलासपुर में जो 66 खिलाड़ी रहते हैं, उनको पुरानी दर के हिसाब से 57 लाख रुपये था जोकि वर्ष 2024 में बढ़ाने के बाद हमने अब लगभग 60 लाख रुपये की राशि दी है। ...(व्यवधान) राकेश जम्वाल जी, **अगर आप अप्लाई करेंगे तो हम इसको करेंगे।**

04.12.2025/1150/av/as/2

प्रश्न संख्या : 3769

श्री भुवनेश्वर गौड़ : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मंत्री जी ने प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया है कि कुल 14 सड़कें खोल दी गई हैं और 6 सड़कों पर अभी तक बसें नहीं चल रही हैं। जवाब में जो इन सड़कों के expenditure likely to be incurred और expenditure incurred up to 31.10.2025 के बारे में लिखा गया है। इन सड़कों के लिए फण्ड्ज की एलोकेशन जीरो बताई गई है और expenditure likely to be incurred लिखा गया है।

ये बहुत महत्वपूर्ण रूट्स हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन फण्ड्ज की एलोकेशन कब तक होंगी ताकि इन सड़कों पर बसें दोबारा से शुरू हो सकें। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जब भी हमारा नेशनल हाईवे टूटता है तो क्या एन0एच0ए0आई0 उसके लिए स्टेट गवर्नमैंट को कम्पनसेट करते हैं क्योंकि सारा ट्रैफिक हमारी लैफ्ट बैंक की सड़क से जाता है। अगर दिया जाता है तो इसके लिए एन0एच0ए0आई0 ने कितना कम्पनसेशन दिया है?

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जो मनाली विधान सभा क्षेत्र से संबंधित सड़कों की जानकारी दी है, उनमें गत् वर्ष भारी बरसात के कारण नुकसान हुआ था। इन्होंने उनकी रेस्टोरेशन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने हेतु यह प्रश्न लगाया है। इन्होंने जैसे खुद कहा कि 14 bus able roads were damaged in August, 2025 in Manali area out of which 6 roads have been restored और 8 को लाइट मोटर व्हीकल के लिए खोल दिया गया है। ये जो बजटरी प्रोविजन के संदर्भ में पूछ रहे हैं तो मैं इनको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं, **खासकर जो रोड्ज हैवी व्हीकल्ज के लिए बंद हैं हम उनको खोलने का पूरा प्रयास करेंगे। जहां पर बजटरी प्रोविजन की कमी है, मैं अपने विभाग से बात करके उसके लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान करवाकर उनको तत्काल प्रभाव से खोलने का प्रयास किया जाएगा।**

इन्होंने दूसरा प्रश्न लैफ्ट बैंक से संबंधित पूछा है। अध्यक्ष महोदय, यह आप भी जानते हैं कि कुल्लू-मनाली में जब-जब भी सड़कों को भारी नुकसान हुआ तो

टीसी द्वारा जारी

04.12.2025/1155/टी0सी0वी0/ए0एस0/-1
प्रश्न संख्या : 3769-- क्रमागत्
लोक निर्माण मंत्री ... जारी

उस समय लैफ्ट बैंक अर्थात कुल्लू से मनाली तक की सड़क के अपग्रेडेशन के लिए समय-समय पर कदम उठाए गए क्योंकि एन0एच0ए0आई0 की जो राइट बैंक पर फोरलेन की सड़क है वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। उनसे भी इसके लिए समय-समय पर डिपॉजिट अमाउंट लिया गया है because this is an offhand question इसलिए इस समय मेरे पास इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं and if I am not mistaken around 9 to 13 crore Rupees have deposited by the NHAI to the Executive Engineer Manali for upgradation and construction of this road. हम इस सड़क के विस्तारीकरण के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस रोड पर बहुत-सारी आवासीय और कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी आती हैं। जब हमने इस रोड के एक्सपेंशन का प्रस्ताव रखा था तब बहुत-सारे लोगों ने

आपत्तियां उठाई थीं क्योंकि इस क्षेत्र में काफी मात्रा में बागीचे, होटल्स और रिजॉट्‌र्स आते हैं। इसके बावजूद हम प्रयास करेंगे कि जितनी डिपार्टमेंट के पास सड़क की एक्वायर्ड विड्‌थ उपलब्ध है उसके तहत इस सड़क को अपग्रेड किया जाएगा क्योंकि वर्ष 2022, 2023 और वर्ष 2025 की आपदाओं में जब मेन नेशनल हाईवे बंद हो गया था तो उस समय यह रोड मनाली क्षेत्र के लिए लाइफलाइन रहा है। यह हमारी प्राथमिकता है और इसमें एन0एच0ए0आई0 से भी सहयोग लिया जाएगा और जितना कार्य हम स्वयं कर सकते हैं वह भी किया जाएगा क्योंकि because this is a connectivity not only to the Manali but even too for the Lahaul & Spiti उस दृष्टि से भी यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सड़क है।

04.12.2025/1155/टी0सी0वी0/ए0एस0/-2

प्रश्न संख्या : 3770

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके अनुसार 7 कार्यालय शिमला से शिफ्ट हुए हैं और एक कार्यालय स्थानांतरित करना विचाराधीन है। जो सात कार्यालय स्थानांतरित किए गए हैं उनमें से एक मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि शिमला को डि-कंजैस्ट करने के प्वाइंट ऑफ व्यू से कार्यालय शिफ्ट किए जा रहे हैं परंतु इसके पैमाने क्या हैं? ये कार्यालय किस आधार पर शिफ्ट किए जा रहे हैं, क्या किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए या किसी अधिकारी को सजा देने के लिए या किसी अन्य आधार पर शिफ्ट हो रहे हैं? क्या सरकार ने इसके लिए नियम या मानक बनाए हैं जिनके आधार पर यह प्रक्रिया हो रही है?

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, शिमला में ट्रैफिक कंजैशन बहुत ज्यादा है। शिमला मूल रूप से 25,000 से एक लाख की पॉपुलेशन के लिए बना था जबकि शिमला के साथ लगते एरिया को मिलाकर 4 से 5 लाख की पॉपुलेशन शिमला में रहती है। सुबह यदि कोई गाड़ी लेकर निकले तो अक्सर एक घंटा ट्रैफिक जाम में रहता है। हमने विभागों के कार्यालय स्थानांतरित नहीं किए बल्कि कमीशन और कुछ विभागों को स्थानांतरित किया है और यह

किसी अधिकारी को सजा देने के उद्देश्य से नहीं किया गया है। हमने कामगार कल्याण बोर्ड को हमीरपुर, कौशल विकास निगम को मंडी, वन्य प्राणी कंजर्वेटर तथा हिमाचल प्रदेश अचल भू संपत्ति को कांगड़ा में स्थानांतरित किया गया है। इसके साथ ही पर्यटन निगम को कांगड़ा और नशा निवारण बोर्ड को हमीरपुर में स्थानांतरित किया गया है तथा पुलिस विभाग के एक पुलिस ट्रेनिंग ऑफिस को भी कांगड़ा में स्थानांतरित किया गया है। प्रदेश में लगभग 1000 करोड़ रुपये की बिल्डिंग्ज खाली पड़ी हुई है और कांगड़ा जिला में सबसे ज्यादा सरकारी बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं। जब सरकारी बिल्डिंग्ज खाली पड़ी है तो इसलिए हमने कहा कि इन बिल्डिंगों का सदुपयोग किया जाए।

एन0एस0 द्वारा जारी ....

4-12-2025/1200/NS-DC/1

प्रश्न संख्या : 3770 -----क्रमागत

मुख्य मंत्री ----जारी

शिमला में हम तकरीबन प्राईवेट बिल्डिंग्ज को किराये के पैसे दे रहे हैं जैस कई भवनों में कमीशन के ऑफिस या अन्य कोई और ऑफिस है। पिछली सरकार ने 1000 करोड़ रुपये के भवन बना कर खाली रखे हैं। जहां-जहां खाली भवन होंगे वहां हमारी सरकार चाहती है कि शिमला को डी-कंजेस्ट किया जाए। जो कार्यालय शिफ्ट हो रहे हैं तो उस कार्यालय के कर्मचारियों से च्वाइस ली जाएगी कि अगर वे शिमला में रहना चाहते हैं तो हम उनको शिमला में ही रखेंगे और उनकी जगह नए कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। किसी को कष्ट या दुःख देने के लिए ये कार्यालय स्थानांतरित नहीं किए जाएंगे। भविष्य में मेरा यह मानना है कि जहां भी भवन खाली हैं जैसे ऊना में बहुत बड़ा भवन खाली है और वहां पर हम स्टेट डिजास्टर मेनेजमैंट का कार्यालय शिफ्ट कर रहे हैं। मण्डी, बिलासपुर और जहां-जहां भवन खाली होंगे वहां सरकार कुछ कार्यालयों को स्थानांतरित करने का विचार रखती है।

प्रश्नकाल समाप्त।

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। ...(व्यवधान) एक मिनट ऊपर हो गया। माननीय सदस्य एक मिनट बैठ जाएं। अभी मैंने मुख्य मंत्री जी का नाम ले लिया है।

4-12-2025/1200/NS-DC/2

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा तारांकित प्रश्न से संबंधित स्पष्टीकरण

मुख्य मुंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि प्रश्न संख्या : 3767 श्री विपिन सिंह परमार जी ने मेरी यात्रा के बारे में पूछा है। उस समय इस बारे में सोशल मीडिया में काफी चर्चाएं हो रही थीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी यह यात्रा निजी थी। जब मैं अपनी बेटी की एडमिशन के लिए लंदन गया तो मैंने कोई भी पैसा सरकारी खर्चे से नहीं किया बल्कि अपने निजी खर्चे से किया है। चाय से लेकर खाने तक सभी की पेमैंट ऑनलाइन की है। टिकट और रहने से लेकर सबकी पेमैंट मैंने अपने निजी पैसों से की है। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह चाहता हूं कि जब हम सब विधायकों के परिवार यात्रा पर जाते हैं तो वे भी अपने पैसे खर्च करें। हालांकि, हमें सुविधा मिलती है कि एम0एल0ए0 अपने फंड से बाहर भी जा सकते हैं। मैंने उसका भी सदुपयोग नहीं किया। मैंने वहां रहने, आने-जाने का सारा खर्चा अपनी निजी पैसों से किया है। इसके लिए एक भी पैसा किसी से नहीं लिया गया और सारा पैसा मेरे अपने अकाउंट से गया है तथा ऑनलाइन पेमैंट की गई है। यहां तक कि हमने वहां पर जो खाना खाया, चाय पी तो उसकी पेमैंट भी ए0टी0एम0 कार्ड से की गई है क्योंकि वहां पर कैश नहीं चलता है। मैं जब सोशल मीडिया में देख रहा था तो व्यक्तिगत तौर पर बहुत बातें और टिप्पणियां हो रही थीं। मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं। श्री विपिन सिंह परमार जी ने ठीक किया कि प्रश्न पूछ लिया। इसलिए मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं।

अध्यक्ष : अब शून्य काल आरम्भ होगा।

नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

4-12-2025/1200/NS-DC/3

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जय राम ठाकुर : मुख्य मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दिया और मुझे लगता है कि यह प्रश्न आपके हित के लिए ही है जिससे सभी चीजें स्पष्ट हो गईं। कई बार क्लेरिफिकेशन देते हुए मीडिया ट्रायल होता है पर चलो अच्छा हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक विषय पर बोलने के लिए समय ले रहा हूं। वह विषय है कि पिछले कल यहां जोरावर स्टेडियम में जो लाठीचार्ज हुआ है और

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

04.012.2025/1205/RKS/डीसी-1

श्री जय राम ठाकुर...जारी

मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उसकी परमिशन नहीं दी गई थी। मेरे पास वह एस0डी0एम0 की चिट्ठी है जिसें मैं यहां लेकर आया हूं। एस0डी0एम0 की ओर से एस0एच0ओ0 को चिट्ठी गई और उसमें मार्च निकालने की पूरी परमिशन दी गई है। वे मार्च करते हुए टैक्सी स्टेंड से जोरावार स्टेडियम की ओर आए। अगर इस चिट्ठी को पढ़कर सुनाना है तो मैं इस पढ़ दूंगा अन्यथा मैं इसे सदन में ले कर दूंगा। मुख्य मंत्री जी को अधिकारी गलत जानकारी देते हैं जिसके कारण आपकी फजीहत होती है। उन्हें मार्च करते वक्त रोका गया और उसके बाद उन पर लाठी चार्ज किया गया। इस लाठीचार्ज में बच्चों की टांगे टूटी और उनके सिर भी फूटे जोकि दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। दूसरा, शिमला में पिछले कल दृष्टिबाधित लोग प्रदर्शन कर रहे थे। एक महिला अधिकारी ने उन्हें डांटकर कहा कि हम मुख्य मंत्री के खिलाफ नारे नहीं सुन सकते। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि राजभवन के सामने माननीय प्रधान मंत्री जी के पुतले को लाते मारी गई और उसके बाद उस पुतले को जलाया गया। उनके खिलाफ नारे लगाए गए, क्या वे नारे उन अधिकारियों को अच्छे लगते थे? आपने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? यह एक चिंता का विषय है। यह हो सकता है कि मुख्य मंत्री के खिलाफ किसी अधिकारी को नारे अच्छे न लग रहे हो लेकिन क्या इस

बात को सार्वजनिक रूप से बोलना उचित है? पिछले कल परमिशन मिलने के बावजूद भी यह कहा गया कि बच्चों को जोरावार स्टेडियम में आने की परमिशन नहीं दी गई थी इसलिए हम इस बात के विरोध में सदन से वाकआउट करते हैं।

(विपक्ष के सभी सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।)

अध्यक्ष : मैं रिकॉर्ड स्पष्ट कर दूं। कल भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था उनको मार्च पास की परमिशन दी गई थी। यद्यपि उन्होंने सड़क पर बैठकर बाधा पहुंचाई और लोगों को आने-जाने से रोका इसलिए पुलिस ने उन पर एक्शन लिया। Yesterday also the Hon'ble Chief Minister has said. ...(Interruption) Today also he wants to make an another Statement. माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

04.012.2025/1205/RKS/डीसी-1

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्य मंत्री टैक्सी स्टेंड से जोरावर स्टेडियम की परमिशन को ले कर रहे हैं। जब वे जोरावार से विधान सभा की तरफ बैरिकेड्स तोड़ कर आगे बढ़ रहे थे तब पुलिस से उनकी हाथापाई हुई। उन्हें टैक्सी स्टेंड से जोरावर स्टेडियम तक किसी ने नहीं रोका। वे साढ़े तीन घंटे तक ट्रैफिक जाम करते रहे। इस दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं कि परमिशन टैक्सी स्टेंड से जोरावर मैदान तक थी जिसकी परमिशन को पूर्व मुख्य मंत्री जी ने ले किया है। ये इस आधार पर रैली में जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं जोकि गलत बात है। पूर्व मुख्य मंत्री कंफ्यूज्ड हैं। उन्होंने चिट्ठी पढ़ कर कहा कि बच्चों को टैक्सी स्टेंड से जोरावर स्टेडियम की परमिशन मिली थी। जोरावर स्टेडियम से बाहर निकलकर उन्हें सड़क रोकने के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई थी। उन्हें विधान सभा तक मार्च करने की कोई परमिशन नहीं थी। विधान सभा के रास्ते पर बैरिकेड्स लगे हुए थे जिन्हें हटाते हुए हाथापाई हुई। इन्हें रैली में जाने के लिए बार-बार फोन आ रहे हैं। इन्होंने वहां जाना है। ये ऐसे ही कह देते कि सत्र समाप्त कर दीजिए हमने रैली में जाना है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर ये किसी मुद्दे पर वाकआउट करते तो ठीक होता परंतु ये लोग राजनैतिक लाभ के लिए यह सारी कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।

शून्य काल

अध्यक्ष : अब शून्य काल होगा। आज 9 माननीय सदस्यों के विषय सदन में प्रस्तुत हुए हैं। पहला विषय श्री बलबीर सिंह वर्मा जी का है जो अनुपस्थित हैं। दूसरा, श्रीमती रीना कश्यप जी का है वह भी अनुपस्थित है। तीसरा विषय श्री सुरेश कुमार जी का है, कृपया आप अपना विषय प्रस्तुत करें।

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न प्रदेश के उन शारिरिक शिक्षकों के बारे में है जिनके पद पिछले कई वर्षों से भरे नहीं गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शारिरिक शिक्षक एक महत्वपूर्ण अंग है।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

04.12.2025/1210/बी.एस./एच.के.-1

शून्य काल

अध्यक्ष : अब शून्य काल आरंभ होगा और 9 माननीय सदस्यों के विषय माननीय सदन में आये हैं। पहला विषय माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा जी का है।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : उपस्थित नहीं।

अध्यक्ष : दूसरा विषय श्रीमती रीना कश्यप जी का है।

श्रीमती रीना कश्यप : उपस्थित नहीं।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी अपना विषय रखेंगे।

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, शून्य काल में मेरा प्रश्न है कि प्रदेश के उन शारीरिक शिक्षकों के बारे में है जिनके लिए पिछले कई वर्षों से पदों को नहीं भरा गया है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और शारीरिक शिक्षक लंबे समय से रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे हजारों शारीरिक शिक्षक जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं वे रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। हमें यह पता है कि स्कूलों में शारीरिक शिक्षा का होना

बड़ा जरूरी है और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इन शिक्षकों का होना बड़ा जरूरी है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या प्रदेश सरकार शारीरिक शिक्षकों के पदों को भरने की इच्छा रखती है? कब तक इन पदों को भरा जाएगा ताकि शिक्षा का सही उद्देश्य पूर्ण हो सके।

Speaker : Anybody wants to intervene-Hon'ble Chief Minister or the Hon'ble Deputy Chief Minister? Okay nobody. This is a very important issue which have been brought before the House by Hon'ble Member Shri Suresh Kumar ji. Definitely for more than three years, there are vacancies of Physical Education Teachers in the school and these vacancies are to be filled up to provide physical education to the students. Therefore, we will ask the Department to fill these vacancies immediately. The reply will be sought from the Department and we will be conveying it to you also and will be placing it on Table of the House and on the record of Vidhan Sabha also. Thank you.

04.12.2025/1210/बी.एस./एच.के.-2

अब अगला विषय माननीय सदस्य श्री डी0एस0 ठाकुर जी का है।

श्री डी0एस0 ठाकुर : उपस्थित नहीं।

अध्यक्ष : अगला विषय श्री दीप राज जी का है।

श्री दीप राज : उपस्थित नहीं।

अध्यक्ष : अगला विषय श्री त्रिलोक जम्वाल जी का है।

श्री त्रिलोक जम्वाल : उपस्थित नहीं।

अध्यक्ष : अगला विषय श्री लोकेन्द्र कुमार जी का है।

श्री लोकेन्दर कुमार : उपस्थित नहीं ।

अब माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी अपना विषय उठाएंगे।

श्री केवल सिंह पठानिया(उप-मुख्य सचेतक)**:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शून्य काल में कृषि एवं पशु पालन मंत्री जी से एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। पिछले कल और उससे पिछले कल भरमौर और चम्बा से माइग्रेट हो करके जो हमरे गद्दी लोग आते हैं उन्हीं में से रोशन लाल जी जो मेरे क्षेत्र ठम्बा का रहने वाला है। पिछले कल उसकी डाडासीबा में 50 बकरियों की मौत हुई है। वह अपने धन को ले जा रहा था उस वक्त यह घटना हुई है। ऐसे ही इंदौरा के अंदर घटना हुई वह बेसिकली कोठी रहने वाला का है। वह रेलू से आगे पठानकोट की तरफ गया है। इसी तरह से ठिंगू राम उसका धन भी अभी कोटला से निकल रहा था उसकी भी 22 बकरियां मरी हैं। क्योंकि 2-3 दिन से यह बहुत बड़ी महामारी फैल रही है। मैं चाहता हूं कि जिस वक्त हमारे गद्दी लोग नीचे को उतरते हैं उस वक्त इनके लिए दवाइंयों का रखरखाव किया जाए। मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि एक स्पैशल टीम वहां जाए जहां-जहां भी हमारे ये गद्दी भाई जा रहे हैं। मैंने विशेषकर जो उल्लेख किया वहां विभाग की टीम जाए। जिला चम्बा और लाहौल के लोग इस तरफ से आते हैं इसलिए विशेष टीम वहां जाए ताकि यह महामारी आगे न बढ़े। यही मैं कृषि एवं पशुपालन मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं।

04.12.2025/1210/बी.एस./एच.के.-3

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी ने जो जानकारी दी है, उस सूचना के आधार पर मैं पशुपालन विभाग के डॉक्टर्ज से कहूंगा कि जहां-जहां भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं उन्हें देंखे कि यह भयानक बीमारी तो नहीं है? जिससे पशुधन को ज्यादा नुकसान हो रहा है। हम इसे बड़ी तत्पर्ता से लेंगे और वेक्सिनेशन और दूसरी सुविधाएं भी उन्हें उपलब्ध करवाएंगे।

अध्यक्ष : अगला विषय डॉ0 जनक राज जी है।

डॉ0 जनक राज : उपस्थित नहीं।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

04.012.2025/1215/डीटी/डीसी-1

कागजात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब कृषि मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

कृषि मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्योनिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा-45(4) के अन्तर्गत चौ0 सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब श्री केवल सिंह पठानिया कार्य सलाहकार समति के 15वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) सभा में प्रस्तुत करेंगे और प्रस्ताव भी करेंगे कि इसे अंगीकार किया जाए।

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समति के 15वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित करता हूं और प्रस्ताव भी करता हूं कि इसे अंगीकार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि माननीय सदन कार्य सलाहकार समिति के 15वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

तो प्रश्न यह है कि माननीय सदन कार्य सलाहकार समिति के 15वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है?

प्रस्ताव स्वीकार।

04.012.2025/1215/डीटी/डीसी-2

विधेयक पर विचार-विमर्श और पारण

अध्यक्ष : अब लोक निर्माण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21) पर विचार किया जाए।

लोक निर्माण मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21) पर विचार किया जाए। माननीय सदस्य इस पर बोल सकते हैं और फिर माननीय लोक निर्माण मंत्री जी इसका उत्तर देंगे। मुझे लगता है कि कोई भी सदस्य इसमें बोलना नहीं चाहता।

तो प्रश्न यह है हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025(2025 का विधेयक संख्यांक 21) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2 व 3 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अब लोक निर्माण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21)को पारित किया जाए।

04.012.2025/1215/डीटी/डीसी-3

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21)को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21)को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025(2025 का विधेयक संख्यांक 21)को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

" हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025(2025 का विधेयक संख्यांक 21) पारित हुआ।"

अध्यक्ष : अब लोक निर्माण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 23) पर विचार किया जाए।
लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 23) पर विचार किया जाए।
अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 23) पर विचार किया जाए। माननीय सदस्य इस पर बोल सकते हैं और फिर माननीय लोक निर्माण मंत्री जी इसका उत्तर देंगे। मुझे लगता है कि कोई भी सदस्य इसमें बोलना नहीं चाहता।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 23) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

04.012.2025/1215/डीटी/डीसी-4

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2-70 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 और 70 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अध्यक्ष : अब लोक निर्माण मंत्री प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 23) को पारित किया जाए।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी

04.12.2025/1220/वाई.के.-एन.जी./1

अध्यक्ष..........जारी

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

पारण :-

अध्यक्ष : अब माननीय लोक निर्माण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 23) को पारित किया जाए।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 23) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 23) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 23) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 23) ध्वनिमत से पारित हुआ।

04.12.2025/1220/वाई.के.-एन.जी./2

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

आज चूंकि वीरवार है और Private Member Day है। जिस कारण अब गैर-सरकारी सदस्य कार्य होगा। दिनांक 28 नवम्बर, 2025 को माननीय सदस्य, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प, यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि "प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने हेतु युवा खेल नीति बनाने पर विचार करे" पर आगे चर्चा होगी। इस चर्चा को माननीय सदस्य, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल इनिशिएट करेंगे। He is absent इसलिए यह संकल्प ड्रॉप हो गया।

अब आज की कार्यसूची में शामिल संकल्पों पर चर्चा होगी। जिसमें पहला संकल्प माननीय सदस्य, श्री त्रिलोक जम्वाल का है। He is also absent so this Resolution is dropped.

अब माननीय सदस्य, श्री जीत राम कटवाल अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे। He is also absent so this Resolution in dropped.

अब माननीय सदस्य, डॉ0 जनक राज अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे। He is also absent so this Resolution is also dropped.

अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार...(व्यवधान) आप प्वाइंट ऑफ ऑर्डर लेना चाहते हैं? ठीक है, माननीय सदस्य, श्री मलेन्द्र राजन, आप अपनी बात रखिए।

04.12.2025/1220/वाई.के.-एन.जी./3

व्यवस्था का प्रश्न

श्री मलेन्द्र राजन : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन का ध्यान अपने इन्दौरा विधान सभा क्षेत्र में हालही में भारी बाढ़ आने के कारण हुए नुकसान की ओर लाना चाहता हूं। मैंने इस विषय को नियम-130 के तहत भी उठाने की कोशिश की थी लेकिन समय की कम उपलब्ध्ता के कारण नहीं बोल पाया। मैंने आज के शून्य काल के लिए भी इस विषय को दिया था और अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष व वर्ष 2023 में भारी बाढ़ आई जिसके कारण मेरे इन्दौरा विधान सभा क्षेत्र के लोगों का बहुत नुकसान हुआ। पोंग डैम से पानी छोड़े जाने के कारण भी काफी नुकसान हुआ। इस बार इन्दौरा टाउन में तारा खड्ड के पानी का बहाव आ गया

और घरों की तरफ घुस गया। ईश्वर की कृपा से वहां पर किसी भी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि यह घटना दिन के समय में हुई थी। वहां पर लोगों के घरों का सामान और दुकानों व व्यवसायिक संस्थानों का काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ-साथ मण्ड के निचले क्षेत्र में भी इस बार भारी बाढ़ के पानी के कारण सड़कों, पुलों और बगीचों का तथा कृषि भूमि का काफी नुकसान हुआ है। दरिया का पानी

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

04.12.2025/1225/वाई0के0-पी0बी0/1

श्री मलेन्द्र राजन ...जारी

काफी गांवों को बीच में से निकल गया है और जगह-जगह पर ऐसी स्थिति बन गई है कि वहां पर तीन-चार जगह मंड मैणी से पराल तक तीन-चार जगह पुल बनाने की जरूरत पड़ गई है। ब्यास नदी ने वहां पर अपना स्थान मोड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी एवं राजस्व मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, इंदौरा में चाहे इंदौरा नगर है, चाहे निचले क्षेत्र मिन्वा, धमोता, मंडमैनी, मंड-स्नोड, मंड-घंडरान, मंड-मलकाना हैं, जहां लोगों का नुकसान हुआ है, उसका स्टीक आकलन करवाया जाए और इनके लिए एक विशेष पैकेज घोषित किया जाए। राजस्व मंत्री जी की अध्यक्षता में पिछले दिनों पोंग डैम एडवाइजरी कमेटी की धर्मशाला में बैठक हुई थी जिसमें माननीय सदस्या श्रीमती कमलेश ठाकुर जी भी मौजूद थी। उस कमेटी में डैम सेफ्टी एक्ट से संबंधित चर्चा भी हुई थी। डैम के पानी के कारण निचले क्षेत्रों को जो नुकसान होता है उसके लिए पोंग डैम की मेनेजमैंट को उसका हर्ज़ाना डाला जाए। हर वर्ष बाढ़ की स्थिति के कारण लोगों का नुकसान होता है। मैं मुख्य मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी से सड़कों व पुलों की बहाली के लिए आग्रह करना चाहूंगा। मुख्य मंत्री जी ने पहले ही किसानों के नुकसान के लिए राहत पैकेज घोषित किया है लेकिन हमारे लोगों को इसका शीघ्र फायदा मिलना चाहिए। इसके अलावा मेन माज़रा के एयरपोर्ट का रोड चक्की खड्ड में बाढ़ के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। इस बार हमारे मलोट के इंडस्ट्री एरिया जिसमें बड़े-

---

बड़े उद्योग लगे हैं उसमें शोंज खड्ड का पानी घुस गया है। मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि इसके लिए भी हमारे विधान सभा क्षेत्र को विशेष पैकेज घोषित किया जाए ताकि लोक निर्माण विभाग या जल शक्ति विभाग की योजनाएं पुनः कार्यान्वित हो सके। हमारे लोगों की सुविधा के लिए शीघ्र सहायाता मिले।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।...(व्यवधान)

Speaker : This is not a Point of Order. माननीय सदस्य श्री मलेन्द्र राजन जी ने एक गम्भीर विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया है। यद्यपि इनसे यह प्रस्ताव नियम-130 के अंतर्गत

04.12.2025/1225/वाई0के0-पी0बी0/2

भी प्राप्त हुआ था लेकिन यह विषय आज के बिजनेस में लिस्टिड नहीं हो पाया। आपने यह विषय शून्य काल में व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से उठाया है। विधान सभा सचिवालय ने इसका संज्ञान लिया है और आपका कंसर्न संबंधित विभाग तक पहुंचा दिया जाएगा तथा इसकी कृत कार्रवाई से आपको और विधान सभा सचिवालय को अवगत करवा दिया जाएगा।

अब इस माननीय सदन की बैठक दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

दिनांक-04.12.2025 **(यशपाल शर्मा)**
धर्मशाला- 176215 **सचिव**